



अपशिष्ट से स्वास्थ्य तक: भारत की स्वच्छता यात्रा

19 नवम्बर 2025

मुख्य बिंदु

- ओडीएफ प्लस गांवों की संख्या 467% वृद्धि के साथ 5,67,708 तक पहुंच गई।
- नवंबर 2025 तक 4692 शहरों को ओडीएफ का दर्जा प्राप्त है।
- 2019 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया।

अवलोकन

सुरक्षित शौचालयों और उचित स्वच्छता तक पहुँच **जन स्वास्थ्य, सम्मान और पर्यावरण की स्थिरता के लिए आवश्यक है**। बेहतर स्वच्छता जलजनित रोगों को कम करती है, उत्पादकता बढ़ाती है और पर्यावरण की रक्षा करती है। यह महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा, गोपनीयता और बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त भी बनाती है। जलवायु परिवर्तन, तेज़ी से बढ़ते शहरी विस्तार और निरंतर असमानता के आज के युग में, सुरक्षित स्वच्छता मानव सम्मान, सामुदायिक कल्याण और सतत प्रगति का आधार बनी हुई है।

भारत के **स्वच्छ भारत मिशन** को अक्सर संयुक्त राष्ट्र निकाय जैसे यूनिसेफ द्वारा विश्व स्तर पर सबसे बड़े स्वच्छता अभियानों में से एक के रूप में रेखांकित किया जाता है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय कार्यवाही किस प्रकार वैश्विक लक्ष्यों में योगदान दे सकती है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर भारत स्वच्छता को एक राष्ट्रव्यापी सफलता की कहानी में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विश्व शौचालय दिवस

विश्व शौचालय दिवस हर साल **19 नवंबर** को वैश्विक स्वच्छता संकट और सभी के लिए सुरक्षित शौचालयों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिवस स्वास्थ्य, सम्मान, समानता और स्थिरता के लिए शौचालयों के महत्व पर प्रकाश डालता है और **सतत विकास लक्ष्य 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता** का प्रत्यक्ष समर्थन करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना है।



स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम): स्वच्छता सुधार के लिए वैश्विक मॉडल

भारत सरकार ने देश भर में स्वच्छता और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। **स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)** एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना और ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है।

स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के बाद से भारत में स्वच्छता अभियान में परिवर्तन देखा गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में बदलाव आया है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (2014) का शुभारंभ:** 2 अक्टूबर 2014 को घोषित इस मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना था। इसके दो घटक हैं: **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (ग्रामीण)** और **स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (शहर और कस्बे)**। इस पहल के अंतर्गत **अक्टूबर 2019** को सभी गांवों, जिलों और राज्यों को **खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ)** घोषित किया गया।

एसबीएम चरण I के परिणाम उल्लेखनीय थे: -

- **स्वास्थ्य लाभ:** डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया है कि 2019 में 2014 की तुलना में डायरिया से होने वाली मौतों में 300,000 की कमी आई है, जो बेहतर स्वच्छता से जुड़ा है।
- **आर्थिक बचत:** ओडीएफ गांवों में रहने वाले परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में प्रति वर्ष लगभग 50,000 रुपये की कमी की।
- **पर्यावरण संरक्षण:** ओडीएफ क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।
- **महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान:** शौचालय की सुविधा बढ़ने से 93% महिलाओं ने अपने घरों में अधिक सुरक्षित महसूस किया।

इन उपलब्धियों के आधार पर, **एसबीएम (ग्रामीण) चरण II ओडीएफ परिणामों को बनाए रखने और 'सम्पूर्ण स्वच्छता'** प्राप्त करने के लिए एकीकृत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

एसबीएम (ग्रामीण) के दूसरे चरण को 2020 में घरेलू शौचालयों तक सार्वभौमिक पहुँच और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल में बदलना है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार करना है, जिससे सभी गांव ओडीएफ प्लस मॉडल बन सकें, जिसमें ओडीएफ स्थिरता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और दृश्य स्वच्छता शामिल है।

Total outlay of INR 1.40 lakh crores to facilitate the transformation of villages from ODF to ODF Plus Model. ^x

ओडीएफ प्लस गाँव

ओडीएफ प्लस गाँव को ऐसे गाँव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है और दृष्टिगत रूप से स्वच्छ है। ओडीएफ प्लस गाँवों के **तीन प्रगतिशील चरण** हैं:

- **ओडीएफ प्लस आकांक्षी:** एक गाँव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है और उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है।
- **ओडीएफ प्लस उभरता हुआ:** एक गाँव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है और उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है।
- **ओडीएफ प्लस मॉडल:** एक गाँव जो अपनी ओडीएफ स्थिति को बनाए रखता है और उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है; दृश्य स्वच्छता का पालन करता है, और ओडीएफ प्लस सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संदेश प्रदर्शित करता है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के क्षेत्र में भारत की प्रगति, पहुँच से लेकर स्थिरता की ओर एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव खुले में शौच मुक्त घोषित होने से लेकर **ओडीएफ प्लस** और **ओडीएफ प्लस मॉडल** का दर्जा प्राप्त करने तक लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे सुविधाओं के रखरखाव में समुदाय की मज़बूत भागीदारी दिखाई दे रही है। इस बीच, शहरी केंद्रों ने **घरेलू और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लक्ष्यों को पार कर लिया है**, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि स्वच्छता का बुनियादी ढाँचा बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बनाए रखे।

ओडीएफ प्लस प्लस: इसका तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां खुले में शौच नहीं होता है और सभी शौचालय कार्यात्मक और अच्छी तरह से अनुरक्षित हैं, और सभी मल और सीवेज को खुली नालियों या जल निकायों में बहाए बिना सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है।

ग्रामीण स्वच्छता (एसबीएम-ग्रामीण)

- 95% से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया।
- ओडीएफ प्लस गांवों में 467% की वृद्धि हुई है - दिसंबर 2022 में 1 लाख से बढ़कर 5.67 लाख गांव हो गए हैं।
- ओडीएफ प्लस आदर्श गांवों की संख्या बढ़कर 4,85,818 हो गई।

शहरी स्वच्छता (एसबीएम-शहरी)

- 4,692 शहर ओडीएफ हैं, 4,314 ने ओडीएफ+ हासिल कर लिया है, तथा 1,973 शहर ओडीएफ++ स्थिति तक पहुंच गए हैं।
- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय:
 - ✓ निर्माण कार्य पूर्ण: 108.62%
 - ✓ निर्मित: 63,74,355
 - ✓ मिशन लक्ष्य: 58,99,637
- सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय:
 - ✓ निर्माण कार्य पूर्ण: 125.46%
 - ✓ निर्मित: 6,38,826
 - ✓ मिशन लक्ष्य: 5,07,587

(19.11.2025 तक)

जल एवं स्वच्छता तालमेल: अमृत एवं जल जीवन मिशन

(अमृत) जैसी पूरक योजनाएँ शहरी सीवरेज और जल निकासी पर केंद्रित हैं, जबकि जल जीवन मिशन घरों तक विश्वसनीय जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है और स्वच्छता परिणामों को मज़बूत बनाता है। ये नीतियाँ मिलकर स्थिरता, समावेशिता और गरिमा पर ज़ोर देती हैं, जिससे स्वच्छता जन स्वास्थ्य और विकास का आधार बनती है।

- अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास पर केंद्रित है। अमृत 2.0 की शुरुआत 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में की गई। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।

➤ 34,447 करोड़ रुपये की लागत वाली 890 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

➤ 4,622 एमएलडी (मिलियन लीटर/दिन) की नई/संवर्धित सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है, जिसमें पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए 1,437 एमएलडी शामिल है।

➤ ₹68,461.78 करोड़ की 586 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

➤ स्वीकृत परियोजनाओं से 6,964 एमएलडी एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) क्षमता बढ़ेगी, जिसमें से 1,938.96 एमएलडी को पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है।

(21.08.2025 तक)

- अगस्त 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन , सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के अलावा, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों की स्वच्छता और रखरखाव पर भी ध्यान केंद्रित करता है ।

निष्कर्ष:

भारत की स्वच्छता यात्रा खुले में शौच की समस्या से निपटने से लेकर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की स्थायी प्रणालियों के निर्माण तक के परिवर्तन को दर्शाती है। स्वच्छ भारत मिशन , अमृत और जल जीवन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से , देश बुनियादी ढाँचे के निर्माण से आगे बढ़कर गरिमा, समावेशिता और दीर्घकालिक स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ, ये प्रयास न केवल जन स्वास्थ्य को मजबूत करते हैं, बल्कि सतत विकास लक्ष्य 6 के तहत वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी हैं , जिससे भारत सभी के लिए सुरक्षित स्वच्छता को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

संदर्भ:

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय:

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2089254>

<https://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx>

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4632_IRzPYO.pdf?source=pqals

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय:

<https://sbmurban.org/#>

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4730_ge4vw3.pdf?source=pqals

https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/sites/default/files/Technical-Notes/10Years_of_SBM_Brochure.pdf

https://sbmurban.org/storage/app/media/pdf/ODF_Plus_and_ODF_PlusPlus.pdf

स्वच्छ भारत मिशन:

<https://swachhbharatmission.ddws.gov.in/>

संयुक्त राष्ट्र:

<https://www.un.org/en/desa/ensure-safe-and-hygienic-sanitation-all-un-urges-marking-world-toilet-day#:~:text=Calendar-.Ensure%20safe%20and%20hygienic%20sanitation%20for%20all%2C%20UN%20urges%2C%20marking.in%20vulnerable%20situations%2C%20by%202030>

पीके/केसी/एनकेएस